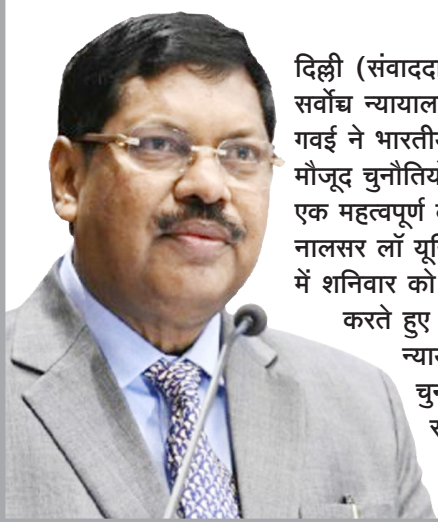


भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार की अत्यंत आवश्यकता, मुख्य न्यायाधीश गवई का बड़ा बयान



दिल्ली (संवाददाता)

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों और सुधार की जरूरत पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। हैदराबाद में नालसर लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शनिवार को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें दशकों तक चलने वाले मुकदमों भी शामिल हैं।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, भारत की कायदेशीर व्यवस्था बड़े-बड़े आव्हानों का सामना कर रही है। इनका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हमारी न्याय व्यवस्था में सुधार की तत्काल जरूरत है। फिर भी, मैं भविष्य को लेकर आशावादी हूँ कि मेरे सहकारी नागरिक इन चुनौतियों का सामना करेंगे और सुधार लाएंगे। उन्होंने विशेष रूप से उन मामलों का जिक्र किया, जहां मुकदमों में देरी के कारण लोग वर्षों तक जेल में रहते हैं और बाद में उन्हें निर्दोष घोषित

किया जाता है। उन्होंने कहा, हमने ऐसे कई मामले देखे हैं, जहां किसी व्यक्ति ने सालों तक जेल में बिताने के बाद अंततः निर्दोष साबित हुआ। मुख्य न्यायाधीश ने नई पीढ़ी पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे इन चुनौतियों से निपटने और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में सक्षम होंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे अपने परिवार पर आर्थिक बोझ डाले बिना विदेशों में स्कॉलरशिप के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उन्होंने कहा, माता-पिता पर निर्भर रहने के बजाय स्कॉलरशिप के जरिए शिक्षा हासिल करें। इसके

अलावा, उन्होंने कानून के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं से आग्रह किया कि वे प्रभाव या रसूख के आधार पर नहीं, बल्कि ईमानदारी और नैतिकता के आधार पर अपने मार्गदर्शक चुनें। इस दीक्षांत समारोह में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीएस नरसिंहा, और तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजय पॉल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अतिरिक्त जानकारी: मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई

ने हाल के वर्षों में न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदमों का समर्थन किया है। उनके नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल तकनीक को अपनाने और ई-कोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने पर जोर दिया है ताकि मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा, उन्होंने निचली अदालतों में बुनियादी ढांचे की कमी और वकीलों की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उनकी यह टिप्पणी भारतीय न्याय व्यवस्था में लंबित मामलों की विशाल संख्या (लगभग

४.५ करोड़ मामले, जैसा कि २०२४ तक के आंकड़ों में बताया गया है) और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि न्याय व्यवस्था को और अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए तकनीकी नवाचार और कानूनी शिक्षा में सुधार जरूरी हैं। यह बयान उस समय आया है, जब भारत में न्यायिक सुधारों की मांग जोर पकड़ रही है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच और वंचित समुदायों के लिए कानूनी सहायता के मुद्दों पर।

दुनिया की सबसे तेज़ बैगेज क्लेम प्रणाली विकसित की जाए-मुख्यमंत्री फडणवीस

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, नवी मुंबई
नवी मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुनिया की सबसे तेज़ बैग क्लेम प्रणाली विकसित की जानी चाहिए और यही इस एयरपोर्ट की एक अनोखी विशेषता बननी चाहिए। उन्होंने यह जानकारी प्रोजेक्ट स्थल का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हवाई अड्डे के कुल निर्माण कार्य का ९४% हिस्सा पूरा हो चुका है, और शेष ६% कार्य सितंबर २०२५ तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद पहला यात्री विमान यहां से उड़ान भरेगा।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ



शिंदे, वन मंत्री गणेश नाइक, पूर्व सांसद रामशेट ठाकुर, विधायक प्रशांत ठाकुर, महेश बालदी, मंदा म्हात्रे, सिडको के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विजय सिंघल, विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, जिलाधिकारी किसन जावळे, सिडको के सह-प्रबंध निदेशक शंतनु गोयल, राजा दयानिधि, गणेश देशमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी सुरेश मेंगडे, गीता पिछई, नवी

मुंबई मनपा आयुक्त कैलास शिंदे, नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारबे, सह पुलिस आयुक्त संजय येनुपूर, और उपायुक्त रश्मी नांदेडकर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि १० जून २०२२ को सिडको द्वारा १,१६० हेक्टेयर की पूरी ज़मीन पर १००% पहुँच और मार्गाधिकार की अनुमति एनएमआईएल को प्रदान की गई। पुनर्वास की सभी

प्रक्रियाएँ पूरी की जा चुकी हैं और सिडको ने ज़मीन अधिग्रहण एवं पुनर्वास पर लगभग २,००० करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

३० जून २०२५ तक इस परियोजना ने ९६.५% भौतिक प्रगति दर्ज की है। फिलहाल लगभग १३,००० कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं और शेष काम के लिए और कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में कार्य सितंबर से पहले पूर्ण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के फेज १ और २ में सालाना २ करोड़ यात्रियों और ८ लाख मीट्रिक टन माल को संभालने की क्षमता होगी। यह हवाई अड्डा सितंबर २०२५ से संचालन के लिए तैयार होगा।

बीड: सर सैयद अहमद खान व पिपल्स माध्यमिक विद्यालय के छात्र हुमैद जावेद ने छात्रवृत्ति परीक्षा में हासिल की बड़ी सफलता

बीड: सर सैयद अहमद खान व पिपल्स माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है। चाहे खेल हो, प्रतियोगी परीक्षाएँ हों या छात्रवृत्ति परीक्षा - यह विद्यालय छात्रों को नियमित रूप से पढ़ाई, मार्गदर्शन एवं अभ्यास के माध्यम से तैयार करता है।

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ के अंतर्गत आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षा में विद्यालय के १७ छात्र सफल हुए, जिनमें से हुमैद जावेद को महाराष्ट्र शासन की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस



उपलब्धि के लिए विद्यालय की ओर से उनका सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सय्यद सलीम साहब उपस्थित थे। साथ ही पिपल्स एजुकेशन सोसायटी के सचिव मुरताक अंसारी साहब, श्री शंकराचार्य इंग्लिश स्कूल के पाशा साहब, युवा उद्यमी मुदस्सिर अंसारी तथा

सर सैयद स्कूल के सचिव अब्दुल वकील सर भी मंच पर उपस्थित रहे। सभी ने हुमैद जावेद को शुभकामनाएं दीं।

विद्यालय के शिक्षकगणों ने भी हुमैद को बधाई दी और हर स्तर से उनकी इस उपलब्धि की सराहना की जा रही है। चारों ओर से उन्हें शुभकामनाओं का वर्षा हो रहा है।

इरतेदाद से बचाव के लिए हर मस्जिद और हर दस घरों पर मक्कब ज़रूरी-मौलाना नदीम सिद्दीकी

हिंदू भाइयों कि भी उपस्थिती



बीड, १२ जुलाई २०२५ (प्रेस विज्ञप्ति): जमीयत उलमा जिला बीड के तत्वावधान में मकातिब-ए-इस्लामिया की अहमियत व ज़रूरत के विषय पर एक भव्य आमसभा का आयोजन वडोणी के सालंबा रोड स्थित आनंद मंगल कार्यालय में किया गया। इस सभा की अध्यक्षता जमीयत उलमा महाराष्ट्र के अध्यक्ष हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब ने की।

कार्यक्रम की शुरुआत मक्कब के छात्र तौहीद इब्ने कलीम की तिलावत-ए-कलाम पाक से हुई, और मक्कब के ही छात्र तौफीक कुरैशी सलमा ने नात शरीफ पेश की। मकातिब के छात्रों का नज़रा-ए-कुरआन मौलाना सैयद नूर साहब की देखरेख में शुरू कराया गया।

मुजतबा अहमद खान सर (उपाध्यक्ष,

जमीयत उलमा मराठवाड़ा) ने वडोणी में चल रहे २३ मकातिब इस्लामिया की प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि वर्तमान में २८५ छात्र-छात्राएं तालीम प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें ५० छात्र नज़रा-ए-कुरआन कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों की मेहनत को सराहनीय बताया।

मुफ्ती अब्दुल्ला कासमी साहब (अध्यक्ष, जमीयत उलमा जिला बीड) ने कुरआन की फज़ीलत पर तफ़सील से रोशनी डाली और उपस्थित सभी श्रोताओं से वादा लिया कि वे खुद भी कुरआन पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। मौलाना अब्दुर्ऊफ साहब ने भी सभा को संबोधित किया।

सभा के अध्यक्ष मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब ने छात्रों की शैक्षणिक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि आज के इस फितनो (विकृतियों)



वाले दौर में मक्कबों की स्थापना बेहद ज़रूरी हो गई है। जो व्यक्ति अपने बच्चों को दीन से दूर रखता है, वह दरअसल उन्हें 'इरतेदाद' की राह पर डाल रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हर मस्जिद के साथ-साथ हर दस घरों पर एक मक्कब होना चाहिए। ताकि स्वस्थ समाज कि रचना हो देश के प्रति मोहब्बत और उसकी प्रगति में योगदान के लिए वो राष्ट्रीय धारे में साथ साथ चले।

उन्होंने यह भी कहा कि जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब बार-बार मुसलमानों को ताकीद करते हैं कि चाहे सूखी रोटी खानी पड़े, लेकिन अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की शिक्षा अवश्य दें और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें।

मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब ने जमीयत

उलमा-ए-हिंद की ओर से चल रही नई सदस्यता मुहिम की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि सदस्यता अभियान ही संगठन की शक्ति का स्रोत होता है। इससे जमात मजबूत और स्थिर होती है। उन्होंने कहा कि इस समय सदस्यता अभियान जारी है, हर एक को इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और जमीयत उलमा-ए-हिंद को मजबूत बनाना चाहिए।

मौलाना मोहम्मद इब्राहीम कासमी साहब (महासचिव, दीन शिक्षण बोर्ड, जमीयत उलमा महाराष्ट्र) ने मक्कब की तालीम की अहमियत, ओलाद की दीन पर तरबियत, बच्चों के साथ समय बिताने, उन्हें अच्छे अखलाक (चरित्र) से सज्जित करने जैसी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि तालीम के साथ-साथ बच्चों की तरबियत भी एक अहम जिम्मेदारी है, जिस

पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है।

जनाब जनाप सर (अध्यक्ष, नगरपालिका वडोणी) ने भी शिक्षा की अहमियत पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम का संचालन व मेहमानों का स्वागत मौलाना मोहम्मद साबिर रशीदी (महासचिव, जमीयत उलमा जिला बीड) ने बखूबी अंजाम दिया।

इस जलसे में क्षेत्र के कई जमीयत उलमा पदाधिकारी, सदस्य, उलेमा, हाफिज, मसाजिद के इमाम, नगर के गणमान्य नागरिक विशेष रूप से:

कारी साद बिन असलम साहब (अध्यक्ष, जमीयत उलमा तहसील मंजलेगांव)

अस्लम भाई कुरैशी (अध्यक्ष, जमीयत उलमा तहसील वडोणी)

मुस्तकीम भाई (उपाध्यक्ष, जमीयत

उलमा तहसील वडोणी)

हाफिज फारूक साहब (महासचिव, जमीयत उलमा तहसील वडोणी)

मुफ्ती शाहनवाज़ साहब कासमी (निगरान, मकातिब जमीयत उलमा तहसील वडोणी)

नगर परिषद बीड के निम्न सदस्यगण: नसीमुद्दीन

सैयद सादिक ज़मां

ज़ैतुल्लाह खान, शाहिद अली खान, फारूक पटेल (गट नेता), अशफाक

इनामदार, डॉ. इमरान खान, शेख जुनैद, शफीकुल इस्लाम, राजू भाई नेकनूर, शतोष

दायवकर, बारी मुंडे, विकास मुंडे, पत्रकार बंधु:

जानी ग्राम मिरकर, हाजी शरीफ, मंडे सहित अन्य लोग भारी संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।

ऐतिहासिक कारंजा टॉवर के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के कार्यों पर रहेगी नज़र!

प्रेस मीडिया का हार्दिक आभार—रमेश गंगाधरे, एस.एम. यूसुफ



बीड (प्रतिनिधि): ऐतिहासिक कारंजा टॉवर के पूर्ण पुनर्निर्माण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ऐसा मत वरिष्ठ समाजसेवी और उद्यमी रमेशराव गंगाधरे एवं स्वतंत्र पत्रकार एस.एम. यूसुफ ने व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने मीडिया के प्रति आभार भी प्रकट किया।

इस विषय में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि ऐतिहासिक कारंजा टॉवर के पूर्ण नवनिर्माण हेतु वर्ष २०१४ से लगातार संघर्ष जारी है। पिछले ११ वर्षों में इस संदर्भ में जिलाधिकारी, मुख्याधिकारी, तहसीलदार ही नहीं, बल्कि जिला पुलिस अधीक्षक तक को भी समय-समय पर निवेदन सौंपे गए हैं। इस

संघर्ष को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता जगत से भी बार-बार आवाज़ मिली है।

इस अभियान को बीड जिले के साथ-साथ अन्य जिलों के समाचार पत्रों का भी भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है। इसी के चलते कारंजा टॉवर का विषय अब केवल बीड शहर या जिले तक सीमित न रहकर पूरे मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में गुंजने लगा है। इस ऐतिहासिक धरोहर के लिए नागरिक स्वयं आगे आकर निजी खर्च से एक-एक कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में जनभागीदारी से कारंजा टॉवर के लिए ५ कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। फिर भी अभी शेष १२ कार्य बाकी हैं।

इन कार्यों के लिए उच्च पदस्थ

अधिकारियों को नियमित रूप से निवेदनों के माध्यम से स्मरण कराया जा रहा है। साथ ही शासन और प्रशासन जागरूक हो, इस उद्देश्य से मीडिया के माध्यम से निरंतर समाचार और लेख प्रकाशित कराए जा रहे हैं।

फिर भी अब तक शासन-प्रशासन की ओर से इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए यह संघर्ष अब भी जारी है और जब तक पूर्ण नवनिर्माण नहीं हो जाता, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा।

ऐतिहासिक कारंजा टॉवर के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के कार्यों पर निगरानी रखी जाएगी, ऐसा स्पष्ट वक्तव्य रमेशराव गंगाधरे और एस.एम. यूसुफ ने दिया है।

बीड नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच हो वरना लोकसेना करेगी आंदोलन-अंड. इलियास इनामदार

बीड (प्रतिनिधि): लोकसेना संगठन ने बीड जिल्हाधिकारी को एक निवेदन सौंपकर मांग की है कि बीड नगर परिषद के भ्रष्ट कार्यों की तुरंत जांच करवाई जाए, अन्यथा लोकसेना संगठन जन आंदोलन करेगा।

लोकसेना का आरोप है कि बीड नगर परिषद के बांधकाम (निर्माण) विभाग में नगर परिषद फंड से करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार किए गए हैं। फर्जी बिल बनाकर, बोगस भुगतान दिखाकर मुख्याधिकारी, निर्माता अभियंता, सहायक अभियंता व कुछ कर्मचारियों ने बड़ी मात्रा में सार्वजनिक निधि का दुरुपयोग किया है।

यह भी कहा गया है कि विभिन्न समाचार पत्रों में इस भ्रष्टाचार से संबंधित खबरें लगातार प्रकाशित हो रही हैं और सामाजिक कार्यकर्ता व आरटीआई कार्यकर्ता इस विषय पर आंदोलन व जांच की लगातार मांग कर रहे हैं।

एक ओर नगर परिषद आम जनता से जबरन टैक्स वसूल रही है, तो दूसरी ओर उस टैक्स की राशि का उपयोग बीड शहर के विकास या बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के बजाय, भ्रष्टाचार में किया जा रहा है।

अधिकारियों द्वारा नकली इस्टीमेट तैयार किए गए हैं और फर्जी बिल बनाकर सरकारी निधि का दुरुपयोग किया गया है।

न केवल निर्माण विभाग बल्कि जल आपूर्ति विभाग और अन्य कई विभागों में भी भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऐसे में बीड

जिल्हाधिकारी से यह मांग की गई है कि जनवरी २०२३ से लेकर वर्तमान जुलाई २०२५ तक का ऑडिट करवाया जाए और इस पूरे भ्रष्टाचार की परतें खोली जाएं। अन्यथा लोकसेना संगठन बड़ा जन आंदोलन छेड़ेगा, ऐसा इशारा लोकसेना प्रमुख अंड. इलियास इनामदार ने जिला प्रशासन को दिया है।



समाज में बढ़ती अपराध दर पर अंकुश लगाने के लिए धार्मिक और नैतिक शिक्षा आवश्यक-प्रोफेसर सलीम इंजीनियर

नई दिल्ली, १२ जुलाई : जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने समाज में बढ़ते अपराध और उसकी रोकथाम विषय पर एक ऑनलाइन धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रो. इंजीनियर ने की। सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु और बुद्धिजीवी शामिल थे। स्वामी सुशील गोस्वामी महाराज, स्वामी लोकांत, फादर नॉर्बर्ट हर्मेन, रब्बी इज़ाकील इसाक मलिकर, मर्ज़बान नरीमन ज़वाला और सिस्टर बी के हुसैन ने सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए।

अपने अध्यक्षीय भाषण में जमाअत के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर सलीम ने समाज में बढ़ते अपराधों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपराधों के विभिन्न रूपों की ओर इशारा करते हुए कहा कि मनुष्य इस धरती पर ईश्वर की सर्वोच्च रचना है। केवल सज़ा कानून बनाकर अपराधों को नहीं रोका जा सकता। जब तक समाज में अपराध के खिलाफ जागरूकता पैदा नहीं होगी, तब तक अपराधों को रोका नहीं जा सकता। अपराध बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि मनुष्य अपने जीवन का मूल उद्देश्य भूल गया है। मानवीय गरिमा की रक्षा सभी धर्मों की मूल शिक्षाओं में निहित है। लेकिन इन सबके बावजूद, मनुष्य अपराध में लिप्त है। उन्होंने कहा कि समाज

में अपराध तेज़ी से बढ़ रहा है। मानवीय रिश्तों का हनन हो रहा है। ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। पत्नी पति की ओर पति पत्नी की हत्या कर रहा है। यहाँ तक कि बुजुर्गों के खिलाफ भी जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि सरकार के समर्थन से होने वाले अपराध ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सरकार को आपराधिक तत्वों का समर्थन बंद करना चाहिए। मीडिया की ज़िम्मेदारी ऐसी बातें प्रसारित करना है जिससे अपराध रोकने में मदद मिले। अदालत की ज़िम्मेदारी असली अपराधी को जल्द से जल्द सज़ा दिलाना है। विश्व स्तर पर हो रहे अपराधों का ज़िक्र करते हुए प्रोफेसर इंजीनियर सलीम ने कहा कि यूक्रेन और फ़िलिस्तीन में मानवता के खिलाफ युद्ध अपराध बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। युद्धग्रस्त इलाकों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की हत्या हो रही है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त अपराधों के खिलाफ लोगों की चेतना जागृत करने की ज़रूरत है। सरकार को शांति और कानून का पालन सुनिश्चित करना चाहिए और एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जो सभी प्रकार के अपराधों से मुक्त हो।

सर्व धर्म संसद के स्वामी सुशील

गोस्वामी महाराज ने एक महत्वपूर्ण विषय पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए उन्होंने जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में होने वाले किसी भी अपराध से पूरा समाज प्रभावित होता है। हमने सरकार से संसद में धार्मिक बहस के अलावा इस मुद्दे पर भी चर्चा करने का अनुरोध किया था। सुशील गोस्वामी महाराज ने कहा कि सभी धर्मगुरुओं को समाज में व्याप्त बुराइयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधों का समाधान के लिए अपराधी को जल्द से जल्द सज़ा दिलाना है। जो सभी धर्मों को नुकसान पहुँचाती है। उन्होंने कहा कि अपराध और हिंसा के लिए किसी एक धर्म को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, ऐसे में सभी धर्मों के लोगों को एक मंच पर आकर इस समस्या के समाधान के बारे में सोचना चाहिए। धर्म के नाम पर हो रही हिंसा की आलोचना करते हुए सुशील गोस्वामी महाराज ने कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा किसी भी तरह स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सभी सकारात्मक सोच वाले लोगों को एक साथ आकर समाज



को अपराध मुक्त बनाना होगा।

इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वामी सर्व लोकांत ने कहा कि जमाअत-ए-इस्लामी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सम्मेलन का आयोजन किया है। यह मुद्दा देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। मेरे विचार से इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य में मानवता लुप्त हो गई है। जिस मनुष्य में धर्म नहीं है, वह पशु के समान हो जाता है। ऐसे में हम अपने भीतर मानवीय मूल्यों को जागृत करने की आवश्यकता है। माता-पिता को अपने बच्चों को उच्च नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। जब समाज में अच्छे

लोग बढ़ेंगे, तो अपराध स्वतः ही समाप्त हो जाएँगे। सबसे पहले हमें स्वयं को सुधारना होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसा ईंसान बनना चाहते हैं। नैतिकता की शिक्षा घर, स्कूल और कॉलेज से शुरू होनी चाहिए। एक आदर्श नागरिक बनने के लिए अच्छे संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अपराध केवल भारत में ही बढ़ रहा है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। सबसे पहले हमें इसके कारणों को

जानना होगा। सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए फादर नॉर्बर्ट हर्मेन ने कहा कि आज मानवीय गरिमा खतरे में है। जीवन मूल्य खतरे में हैं। समाज में असमानता और अन्याय बढ़ा है, जिसके कारण अपराध भी बढ़े हैं। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। मानवीय मूल्यों को बढ़ावा मिलने पर ही सभी प्रकार की बुराइयाँ दूर होंगी। रब्बी इज़ाकील इसाक मलिकर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में आध्यात्मिक प्रकाश फैलाने की आवश्यकता है। ईश्वर दयालु और क्षमाशील है। धर्म में समानता और करुणा का भाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गंभीर आपराधिक मामले वर्षों तक अदालतों में लंबित रहते हैं, जिससे असली दोषियों को सजा नहीं मिल पाती। अगर न्यायालय अपने काम में तेज़ी लाएँ, तो आपराधिक मामलों की संख्या कम हो सकती है। अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति पर, मर्ज़बान नरीमन ज़वाला ने अपराधों के मनोवैज्ञानिक पहलू पर प्रकाश डाला और कहा कि अपराध हर युग में होते रहे हैं। सवाल यह है कि इन्हें कैसे रोका जाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने की ज़रूरत है। एक निश्चित उम्र के बाद ईंसान अपराध की ओर आकर्षित हो

जाता है। अगर लोगों को कम उम्र से ही अपराध के नुकसान के बारे में शिक्षित किया जाए, तो इस पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इसकी शुरुआत घर से ही हो सकती है। अगर नई पीढ़ी को अपराध से बचना है, तो अभिभावकों और स्कूलों को इसके लिए तैयार करना होगा। सिस्टर बी के. हुसैन ने कहा कि पूरा समाज नैतिक पतन की ओर बढ़ रहा है। समाज में अपराध बढ़ने के कई कारण हैं। हमें इन कारणों पर गंभीरता से विचार करना होगा। स्वयं को न समझ पाना ही इसका मुख्य कारण है। मनुष्य भूल गया है कि वह कौन है और उसका कर्तव्य क्या है। व्यक्तिवाद और स्वार्थ अपराधों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। धर्म के नाम पर व्याप्त हर संकीर्णता को त्यागना होगा। सभी मनुष्य भाई-बहन हैं। ईश्वर और समाज से जुड़ें। अगर हम समाज में प्रेम और भाईचारा फैलाएँ, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। सम्मेलन के अंत में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर इंजीनियर सलीम ने घोषणा की कि इस ऑनलाइन सम्मेलन के बाद, जमाअत-ए-इस्लामी जल्द ही इसी विषय पर एक बड़े पैमाने पर ऑफलाइन सम्मेलन का आयोजन करेगी। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के सहायक सचिव वारिस हुसैन इस ऑनलाइन सम्मेलन हुवा।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार २०२५: न्यूयॉर्क में अंड.वर्षाताई देशपांडे सम्मानित

बीड प्रतिनिधि: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार एक प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार है, जो इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को १९८३ में और जे.आर.डी. टाटा को १९९२ में प्राप्त हुआ था। ३३ वर्षों के लंबे अंतराल के बाद यह पुरस्कार भारत को अंड. वर्षाताई देशपांडे के रूप में प्राप्त हुआ है। यह सभी भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान की बात है, जैसा कि लेक लाडकी अभियान के बाजीराव ढाकणे ने कहा।

न्यूयॉर्क में अंड. वर्षाताई देशपांडे को कन्या भ्रूण हत्या रोकने, लड़कियों के जन्म का स्वागत करने और उनके सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (पण्डन-२) द्वारा सम्मानित किया गया। हमें यह बताने हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अंड. वर्षाताई देशपांडे, सचिव, दलित महिला विकास मंडल, सातारा और लेक लाडकी अभियान की मुख्य प्रवर्तक, को संयुक्त राष्ट्र के 'यूनाइटेड नेशन्स पॉप्युलेशन अवॉर्ड २०२५' से पुरस्कृत व्यक्ति (डोरीश-

रीश) के रूप में सम्मानित किया गया है।

'यूनाइटेड नेशन्स पॉप्युलेशन अवॉर्ड' प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य' के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। १९८३ में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और यह वैश्विक स्तर पर एक अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अंड. वर्षाताई देशपांडे को यह पुरस्कार लिंग आधारित भ्रूण चयन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए दिया गया है। इस कार्य में उन्होंने क्षमता निर्माण, जनजागरूकता, कानूनी कार्रवाई और सामुदायिक सहभाग के सभी स्तरों पर उल्लेखनीय योगदान दिया है।

इससे पहले यह पुरस्कार भारत को व्यक्तिगत श्रेणी में आयनन लेडी इंदिरा गांधी (१९८३) और विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा (१९९२) के माध्यम से प्राप्त हुआ था। इस वर्ष यह पुरस्कार अंड. वर्षाताई देशपांडे

को ११ जुलाई २०२५ को न्यूयॉर्क में प्रदान किया गया।

वर्षाताई देशपांडे के कार्यों का विवरण: अंड. वर्षाताई देशपांडे ने बीड जिले सहित महाराष्ट्र में बाल विवाह को रोकने और ऐसी लड़कियों को शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए 'लक्ष्मी मुक्ति' अभियान के तहत महिलाओं को संपत्ति में पति के साथ सह-मालिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया, विशेष रूप से कृषि भूमि के संदर्भ में। इसके लिए उन्होंने महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने का कार्य भी किया।



पुरस्कार समारोह: यह पुरस्कार ११ जुलाई २०२५ को न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया, जिसमें अंड. शैलजाताई जाधव, कैलास जाधव और दलित महिला विकास मंडल, सातारा के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बाजीराव ढाकणे ने कहा कि अंड. वर्षाताई देशपांडे को प्राप्त यह वैश्विक स्तर का यूनाइटेड नेशन्स पॉप्युलेशन अवॉर्ड २०२५ महाराष्ट्र की महिलाओं और लड़कियों के लिए एक सम्मान है। अतिरिक्त जानकारी: अंड. वर्षाताई देशपांडे एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हैं, जिन्होंने विशेष रूप से दलित और वंचित समुदायों की महिलाओं और लड़कियों के उत्थान के लिए अपना जीवन

समर्पित किया है। उनके नेतृत्व में 'लेक लाडकी अभियान' ने महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या और लिंग भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया है। उन्होंने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए, जिनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समुदायों को शिक्षित करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना शामिल है। उनकी कानूनी विशेषज्ञता ने कई मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सरकारी नीतियों और योजनाओं को लागू करने में भी योगदान दिया है, जो महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं।

वर्षाताई का कार्य न केवल महाराष्ट्र तक सीमित है, बल्कि उनके प्रयासों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा उनकी उपलब्धियों को मान्यता देना इस बात का प्रमाण है कि उनका कार्य वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है।

सीसीएमपी डॉक्टर नोंदणी पर आय एमएफएर टिका

जिंतूर (एम एजाज जिंतूरकर) सी सी एम पी कोर्स किये हुए! होमियोपैथिक डॉक्टर नोंदणी प्रक्रिया पर आय एम ए संघटना के भुमिका पर परभणी जिल्हा होमियोपैथिक डॉक्टर असोसिएशन ने टिका टिप्पणी की है! दि १०जुलाई को

तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री को भेजा गया! निवेदन परभणी जिल्हा होमियोपैथिक डॉक्टर असोसिएशन



शाखा जिंतूर की ओर से निवेदन में कहा गया है! के आय एम ए पदाधिकारियों की ओर से सोशल मीडिया पर झूठी और दिशाभूल करनेवाले माहिती फैलाई जा रही है! ऐसा आरोप लगाया है! स न २०१४ में कायदे में सुधारणा कर ये कोर्स को मान्यता दी गई है! ३० जुन २०२५ को शासन ने नोंदणी को लेकर अधिकृत आदेश निकाला है! बड़े बड़े हॉस्पिटल में

ये ही डॉक्टर्स आय सी युऔर ,आर एम ओपद पर कार्यरत होते हुए! भी नोंदणी के समय में विरोध कर रहे हैं! ऐसा निवेदन मे कहा गया है! किसी भी दबाव में ना आकर सी सी एम पी डॉक्टरों की नोंदणी जल्द पुरी की जाये! ऐसी मांग

परभणी जिल्हा होमियोपैथिक डॉक्टर असोसिएशन शाखा जिंतूर की ओर से की गई है! निवेदन पर डॉ इरफान खान

साहब खान आगाई डेसल, डॉ शेख अतिख, डॉ सतोष पटेलमुख, डॉ अशोक खके, डॉ सचिन कडे, डॉ अजिम सिद्दीकी, डॉ गोपाल शर्मा, डॉ योगेश तुरे, डॉ जयकांत हांके, डॉ सुमेर मोहारे, डॉ विठ्ठल काकडे, डॉ नगमा डागरा , डॉ गडे आफरिन, डॉ फारुख शेख, डॉ प्रादुर् पंडित, डॉ प्रियंका ठाकुर,आदी के हस्ताक्षर हैं!

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafuiddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com